



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016” पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2016)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये—

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:—

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

- धारा 17 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005(जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 17 की वर्तमान उपधारा (11) के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:—
11(जज) पंजीयन आवेदन पत्र में घोषित बैंक खाते या खातों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य बैंक खाते या खातों के माध्यम से कारोबारी संव्यवहार प्रारम्भ किया जाता है या बैंक खाता बन्द किया जाता है; या

- धारा 25 का संशोधन 3. "मूल अधिनियम" की धारा 25 की उपधारा (9) के शीर्षक व खण्ड (क), खण्ड (ड), खण्ड (च) तथा खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक व खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात्—

(9) टैक्स ऑडिट तथा टैक्स ऑडिट कर निर्धारण:

(क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी व्यौहारी, जो इस प्रयोजन हेतु चयनित किया गया है, के अभिलेख, स्टॉक एवं इससे सम्बन्धित दस्तावेजों का टैक्स ऑडिट, व्यौहारी द्वारा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अथवा सावधिक तथा अन्तिम विवरणियों की शुद्धता और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ सहित विभिन्न दावों की ग्राह्यता का परीक्षण करने के लिये, किया जा सकता है,

परन्तु यह और कि किसी कर निर्धारण वर्ष के टैक्स ऑडिट हेतु किसी कर निर्धारण वर्ष के अन्त से पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी व्यौहारी का चयन नहीं किया जायेगा।

(ड) टैक्स ऑडिट करने वाले अधिकारी को इस अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा उन्हें लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण अथवा प्रतिलिपियाँ लेने अथवा लिवाने, स्टॉक की फेहरिस्त, ऐसी सूचना अथवा विवरण, जो कि इस अधिनियम के अधीन

किसी कार्यवाही में लाभदायक अथवा प्रासंगिक हो, को लेने की शक्ति भी प्राप्त होगी। व्यौहारी ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को पूर्ण सहयोग और सहायता उपलब्ध करायेगा।

यदि व्यौहारी, टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण लेने अथवा प्रतिलिपियाँ, स्टॉक की फेहरिस्त लेने और टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित सूचना अथवा विवरण प्राप्त करने से रोकता है अथवा बाधित करता है अथवा ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को सहयोग नहीं करता है तथा सहायता प्रदान नहीं करता है तो टैक्स ऑडिट का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक अनुपालन के लिये रु0 10,000/- तक का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है। ऐसा कोई अर्थदण्ड व्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा। देयों की वसूली से सम्बन्धित प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के लिये लागू होंगे।

(च) टैक्स ऑडिट प्राधिकारी स्वयं द्वारा एकत्रित अथवा कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त;

(एक) पूर्व में पारित स्वतः कर निर्धारण या कर निर्धारण आदेश की पुष्टि कर सकता है; या

(दो) स्वतः कर निर्धारण या कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर सकता है और व्यौहारी के आवर्त एवं कर को पुनर्निर्धारित कर सकता है; या

(तीन) यदि कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है तो व्यौहारी द्वारा दिये जाने वाले कर की राशि को निर्धारित कर सकता है;

परन्तु कोई कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण व्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अभिनिश्चित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन वाद की सुनवाई हेतु किसी व्यौहारी को तीन स्थगन से अधिक अनुमन्य नहीं होंगे;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए परिसीमा काल हेतु इस अधिनियम की धारा 32 लागू रहेगी।

(छ) टैक्स ऑडिट प्राधिकारियों को कर निर्धारण अधिकारियों की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

धारा 29 में 4. "मूल अधिनियम" की धारा 29 का शीर्षक व उपधारा (1) के स्थान पर संशोधन

निम्नलिखित उपधारा (1) तथा इस उपधारा में खण्ड (घ) के बाद नया खण्ड (घघ) का जोड़ा जाना एवं उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक व उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

29. उस आवर्त, जिसका वर्ष के दौरान कर निर्धारण नहीं किया गया हो या कम दर से किया गया हो, निर्धारण करना :

(1) यदि किसी व्यौहारी के किसी वर्ष या उसके भाग के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कर अवधि के सम्बन्ध में व्यौहारी का सम्पूर्ण आवर्त या उसका कोई भाग;

(घघ) प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र के आधार पर, कर निर्धारण के दौरान, छूट अथवा रियायत प्रदान की गयी हो परन्तु तदुपरान्त ऐसे प्रस्तुत घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र झूठे या गलत पाये जाये; या

(4) यदि कमिश्नर स्वयं या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर संतुष्ट है कि ऐसा करना न्यायोचित और समीचीन है, कर निर्धारक प्राधिकारी को इस निमित्त प्राधिकृत कर सकता है और इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण करने में मत परिवर्तन भी अन्तर्ग्रस्त हो, तो ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी किया जा सकता है किन्तु ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छः वर्ष की समाप्ति अथवा उस आदेश के दिनांक जिसका पुनः कर निर्धारण किया जाना हो, से चार वर्ष की समाप्ति, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

धारा 31 का 5. "मूल अधिनियम" की वर्तमान धारा 31 हटा दी जायेगी।
निरसन

धारा 32(6) 6. "मूल अधिनियम" की वर्तमान धारा 32(6) हटा दी जायेगी।
का निरसन

धारा 34 का 7. "मूल अधिनियम" की धारा 34 की उपधारा (17) के बाद निम्नलिखित नयी संशोधन

(17क) इस अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (14) के अधीन यदि कोई धनराशि, जो किसी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को दिया जाना अपेक्षित हो, परन्तु ऐसा व्यक्ति वह धनराशि अदा करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो देय राशि से अनधिक हो, दायी होगा।

धारा 34—क 8. "मूल अधिनियम" की वर्तमान धारा 34 के बाद निम्नलिखित नयी धारा का

अन्तःस्थापन

34—क. प्रथम प्रभार का दायित्व :

किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि, यदि कोई है, जो किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की जानी है, ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।

धारा 51 में 9. "मूल अधिनियम" की धारा 51 में

संशोधन

(एक) वर्तमान उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (4क) जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

(4क) इस धारा में किसी अन्य बात के होते हुये भी,

(i) एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा विवादित कर या अर्थदण्ड की राशि का पाँच प्रतिशत या रुपये एक लाख की धनराशि, जो भी न्यूनतम हो, भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(ii) एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश या अर्थदण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य आदेश के विरुद्ध की गयी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा विवादग्रस्त धनराशि का बीस प्रतिशत या रुपये पाँच लाख जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

(iii) किसी करमुक्ति या रियायती दर के आवर्त का घोषणा या प्रमाण पत्र, जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो या कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, के सम्बन्ध में अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने अस्थीकृत या प्रस्तुत नहीं किये ऐसे घोषणा या प्रमाण पत्र के आवर्त की राशि पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य कर की दर से कर के दस प्रतिशत के बराबर भुगतान का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

स्पष्टीकरण : उक्त धनराशि उपधारा (6) के अन्तर्गत दिये गये स्थगन की शर्तों के अतिरिक्त होगी।

(दो) वर्तमान उपधारा (8) के वर्तमान तीसरे प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्ध रख दिया जायेगा; अर्थात्—

प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (ग) में दिये गये निर्देशों के उपरान्त पारित नये आदेश के विरुद्ध अपील करने पर पुनः खण्ड (ग) में नया आदेश पारित करने हेतु निर्देश नहीं दिया जायेगा।

धारा 53 में
संशोधन

10. "मूल अधिनियम" की धारा 53 की वर्तमान उपधारा (8) का दूसरा प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा।

धारा 58 में
संशोधन

11. "मूल अधिनियम" की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के खण्ड (xv) के के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्—

(1) (xv) प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये रूपये दस हजार से अनधिक धनराशि;

धारा 61 में
संशोधन

12. "मूल अधिनियम" की धारा 61 की वर्तमान उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्दावली "6 वर्ष" के स्थान पर शब्दावली "8 वर्ष" रख दी जायेगी।

आज्ञा से,
जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016

Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 02 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2016.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2016

(Act No. 02 of 2016)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty seventh year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax, (Amendment) Act, 2016.

(2) This shall come into force at once

Amendment of Section 17 2. In Section 17 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005(hereinafter referred to as the "Principal Act") after Clause (h) of sub-section(11), the following clause shall be added; namely -

(11)(hh) If the transaction in connection of business is initiated through any other bank account or accounts other than the bank account or accounts declared in the registration application or effects the closing of the bank account; or

Amendment in Section 25 3. In Section 25 of the "Principal Act", the heading of sub-section (9) and for the existing clause (a), clause (e), clause (f) and clause (g) of sub-section(9), the following shall be substituted; namely -
(9) Tax Audit And Tax Audit Assessment :

(a) Notwithstanding anything contained in this Act tax audit of records, Stock and related documents of a dealer, selected for this purpose may be conducted for the purpose of ensuring the compliance by the dealer for the requirements of the Act or for examining the correctness of periodical and final returns and admissibility of various claims including input tax credits;

Provided that no dealer may be selected for tax audit for an assessment year after the expiration of five year from the end of such assessment year.

(e) The officer conducting the tax audit shall have powers under section 42 of the Act and may also make or cause to be made extracts or copies from the books of accounts and other documents, inventory of stock, seek such information or statement, which may be useful and relevant to any proceeding under this Act. The dealer shall provide full co-operation and assistance to the audit party during the course of audit;

If the dealer prevents or obstructs the officer from making extracts or copies from the books of accounts and other documents, inventory of stock or from seeking such information or statements required for the purpose of tax audit or does not cooperate and assist the audit party during the course of audit, the officer in charge of the tax audit may impose a penalty upto Rs. 10,000/ for each non compliance. No such penalty shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer. The provisions relating to recovery of dues shall mutatis mutandis apply for recovery of imposed penalty;

(f) The tax audit authority shall after considering all the evidence collected by him or produced in course of the proceeding may :-

- (1) Confirm the self assessment or assessment order which has already been passed; or
- (2) Set aside the self assessment or assessment or reassessment order and reassess the turnover and tax of the dealer; or
- (3) Assess the amount of tax due from the dealer if no assessment has been made so far;

Provided that no such assessment or reassessment shall be made unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer;

Provided further that not more than three adjournments shall be granted to a dealer for hearing of the case under this Section;

Provided further that period of limitation for making Assessment or Reassessment under this section shall be applicable as per section 32 of this Act.

(g) The tax audit officers shall have all the powers of an Assessing Authority.

**Amendment in
Section 29**

4. In Section 29 of the "Principal Act", the heading of existing Section 29, and for the sub-section(1) the following heading and sub-section (1), and after clause (d) of this sub-section, the new following clause (dd) shall be added and for the sub-section (4), the following sub-section shall be substituted; namely –

29. Assessment of the Turnover not Assessed or Assessed at lesser rate during the year :

(1) Where for any year or part thereof, the Assessing Authority has reason to believe that the whole or any part of turnover or tax of the dealer in respect of any tax period has –

(dd) During Assessment rebate or concession has been allowed on the basis of submitted declaration form or certificate but such submitted declaration form or certificate is found to be false or wrong, afterwards; or

(4) If the Commissioner on his own or on the basis of reasons recorded by the Assessing Authority is satisfied that it is just and expedient so to do, he may authorise the Assessing Authority in that behalf, and then such assessment or reassessment not made after the expiration of six years after the end of such assessment year or after the expiration of four year from the date of the order sought to be reassessed, whichever is later notwithstanding that such assessment or reassessment may involve a change of opinion.

**Deletion of
Section 31**

5. Section 31 of the "Principal Act" Shall be deleted.

**Deletion of
Section 32(6)**

6. Section 32(6) of the "Principal Act" Shall be deleted.

**Amendment in
Section 34**

7. In Section 34 of the "Principal Act", after the existing sub-section (17), the following new sub-section (17A) Shall be added; namely–

(17A) If any amount is to be paid by a person to the Assessing Authority, under sub-section (14) of Section 34 of this Act, but the person fails to pay the amount, such person shall be liable to pay such amount not exceeding the amount due, as penalty, as directed by the Assessing Authority in writing, after giving him the opportunity of being heard.

**Addition of
Section 34A**

8. After the existing Section 34 of the "Principal Act", the following new Section 34-A Shall be added; namely –

34A. Tax to be first Charge :

Notwithstanding anything to the contrary, contained in any law or contract, any amount of tax, penalty or other amount, if any, payable by a dealer or other person under this Act shall be first charge on the property of the dealer or such person.

**Amendment in
Section 51**

9. In Section 51 of the "Principal Act"-

(1) After the existing sub-section (4), the following new sub-section (4A) Shall be added; namely –

(4A) Notwithstanding anything contained in this Section,

(i) no appeal against an ex-parte order shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of sum equal to five percent of the amount of disputed tax or penalty or Rupees One Lakh which ever is less;

(ii) no appeal against any other order, besides ex-parte assessment order or penalty shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of sum equal to twenty percent of the amount of disputed tax, penalty or any other amount or Rupees Five Lakh which ever is less;

(iii) no appeal, against any declaration form or certificate of turnover of concession or rebate, which is being rejected by the Assessing Authority or which are not being produced before the Assessing Authority, shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of a sum equal to ten percent of the amount at general rate of

tax payable under this Act, on the amount of the turnover of such declaration form or certificate, rejected or not produced.

Explanation: The above mentioned amount shall be in addition to the condition of the stay given under Sub-Section (6).

(2) After the existing third proviso of sub-section (8), the following new proviso shall be added; namely –

Provided further that on an appeal, against an order passed after the direction under Clause (c), no further direction to pass a fresh order be made under Clause (c).

Amendment in Section 53 10. In Section 53 of the "Principal Act", the existing second proviso of sub-section (8) shall be deleted.

Amendment in Section 58 11. In Section 58 of the "Principal Act", for the existing clause (xv) of sub-section (1), the following sub-section shall be substituted; namely –

(1)(xv) A sum not exceeding rupees ten thousand for each default.

Amendment in Section 61 12. In Section 61 of the "Principal Act", the word "six years" occurring therein sub-section (1), the words "eight years" shall be substituted.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

कारण एवं उद्देश्य

वर्तमान में ब्यौहारियों द्वारा जिन बैंक खातों के माध्यम से कारोबार का लेन-देन होता है, उन बैंक खातों को सम्बन्धित क०नि० अधिकारियों को सूचित करने हेतु अधिनियम एवं नियम में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे ब्यौहारियों द्वारा कारोबार के सम्बन्ध में विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से किये गये लेने-देन की जांच की जा सकनी सम्भव नहीं है। उक्त जांच को सम्भव बनाने के उद्देश्य से धारा 17 की उपधारा (11) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2- टैक्स ऑडिट अधिकारी को प्रभावी बनाये जाने हेतु तथा नियमित कर निर्धारण में कतिपय महत्वपूर्ण वादों का निस्तारण अपेक्षित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण तथा detailing से करने के लिये टैक्स ऑडिट में कार्यरत अधिकारियों को कर निर्धारण अधिकारियों की शक्ति दिया जाना आवश्यक है ताकि वादों की जांच ऑडिट उपरान्त प्राप्त तथ्यात्मक सूक्ष्मता के साथ सम्पादित की जा सके। इस अनुक्रम में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 25 (9) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

3- विगत समय में फॉर्मों के सत्यापन नहीं होने के काफी मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं जो कालबाधित होने के कारण धारा 29(4) से आच्छादित नहीं हो पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में विधिक रूप से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने के कारण राजस्व की हानि होती है। अतः फॉर्मों के गलत पाये जाने पर पुनः कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान न होने के कारण धारा 29 के शीर्षक तथा उपधारा (1) में संशोधन कर स्पष्ट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार उपधारा (4) में पुनः कर निर्धारण की समयसीमा कर निर्धारण वर्ष से छः वर्ष तक करने के साथ-साथ कर निर्धारण आदेश पारित होने के चार वर्ष पश्चात् तक का प्रावधान किया गया है।

4- उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत वाद के एकपक्षीय निस्तारित होने के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा अनेक बार प्रार्थना पत्र पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण कार्यालय का समय एवं शक्ति उक्त वाद के निस्तारण में अनावश्यक रूप से व्यय होती है, जबकि राजस्व हित में उक्त का कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसके अतिरिक्त धारा 31 प्रार्थना पत्र अनिस्तारित रहने की दशा में बकाया वसूली स्थगित रहती है, जिसके कारण बकाया में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। अतः धारा 31 में कर निर्धारण अधिकारी की एकपक्षीय आदेश को पुनः सुनवाई हेतु खोलने की शक्ति को समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। धारा 32(6) में धारा 31 के अन्तर्गत खोले गये वाद के सम्बन्ध में समय सीमा नियत की गयी है जिसे समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

5- वर्तमान में धारा 34(17) में ऐसे ब्यौहारी जिनके विरुद्ध बकाया है, सम्बन्ध में किसी अन्य संस्था यथा बैंक आदि के पास धनराशि होने पर उक्त बैंक आदि से जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा भेजे गये नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर अर्धदण्ड का प्राविधान करने के उद्देश्य से धारा 34 में उपधारा (17क) जोड़ा जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

6- ब्यौहारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किये जाने पर उसकी परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार वाणिज्य कर विभाग का होने के उद्देश्य से ताकि राजस्व की समुचित सुरक्षा की जा सके, धारा 34क जोड़ा जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

डा० इन्दिरा हृदयेश,
वित्त मंत्री।